



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215709
CG-DL-E-27012020-215709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]
No. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

[मामला सं. (ओआई) - 33/2019]

विषय: चीन जन. गण. से एनिलिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/42/2019-डीजीटीआर.—1. मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे आगे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित से एनिलिन (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा पीयूसी अथवा "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. से डंप किए गए आयात के कारण सामग्री की क्षति और घरेलू उद्योग के लिए सामग्री की क्षति का खतरा पैदा हो रहा है और इसने या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं के

आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। चीन जन. गण. से (जिसे यहां आगे "विषय देश" कहा गया है)।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन ऑयल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी तेलीय द्रव है और एक प्राथमिक एमिन कंपाउंड है। इसका रंग नये सिरे से डिजिटल किये जाने पर हल्के पीले द्रव में परिवर्तित हो जाता है। रोशनी अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स, डाई और डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य एक आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।

4. संबद्ध सामान कोड 29214110 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध सामान जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों की "समान वस्तु" माने जा रहे हैं।

घरेलू उद्योग

6. यह आवेदन पत्र मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एक मात्र उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से किया गया है।

आरोपित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

7. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर विश्वास किया है और यह कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन की घरेलू लागतें और कीमतें तब तक स्वीकार नहीं की जा सकतीं जब तक चीनी निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था के परीक्षण पास न कर लें। उपर्युक्त गैर बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं के मद्देनजर और चीन से उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा उसका खंडन किए जाने के अध्याधीन चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का आंकलन नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

8. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण हेतु एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में लिया जाना चाहिए और बेल्जियम से जर्मनी को बिक्री कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की है।

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे पर जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी किए जाने के 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियां दें। इस जांच के लिए चीन के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में यूरोपीय संघ के दावे की विस्तृत जांच होने तक प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बेल्जियम से जर्मनी को बिक्री कीमत ली है।

निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार और पत्तन व्यय के निमित्त समायोजन किए गए हैं।

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

12. घरेलू उद्योग को क्षति के मूल्यांकन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती तथा कीमत न्यूनीकरण प्रभाव, भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसका निष्पादन उत्पादन, बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह में गिरावट के संबंध में घरेलू उद्योग के लिए बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि चीन से आयातों में वृद्धि की भारी दर, चीन में संबद्ध सामानों की काफी क्षमताओं और घरेलू बिक्री कीमतों पर आयात कीमतों के ह्रासमान प्रभाव के मद्देनजर घरेलू उद्योग को और भी क्षति का खतरा है। इसका पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि क्षति हो रही है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत पूर्ण लिखित आवेदन पत्र के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को क्षति और उस आरोपित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और जो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध है।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

15. आवेदक ने जांच की अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) प्रस्तावित की। प्राधिकारी ने भी जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) मानी है। क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांत अपनाए जाएंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित होने के लिए ज्ञात भारत में आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से पूरी संगत सूचना दायर कर सकें।

18. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किये जाएंगे:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

- i. गोपनीय चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)
- ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

23. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

24. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

25. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह

दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

26. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

27. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

28. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल की निरीक्षण

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2020

[Case No, (OI) 33/2019]

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Aniline from China PR.

F. No. 6/42/2019-DGTR.—1. M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as “petitioner” or “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (herein referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (herein referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein also referred to as the “Rules”) for original Anti-Dumping investigation on imports of Aniline (hereinafter referred to as or “product under consideration” or PUC or “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “Subject country”)

2. The Applicant has claimed that material injury and a threat of material injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports from China PR and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

Product under consideration

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil”. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when

exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.

4. The subject products are classified under Chapter Heading 29 under the code 29214110. The customs classification is indicative only and in no way it is no way binding upon the product scope.

Like article

5. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the Applicant and those exported from subject country. The Applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the Applicant are being treated as 'like article' of the subject goods imported from the subject country.

Domestic industry

6. The application has been filed by M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. The Applicant is the sole producer of the subject goods in India. The Applicant has claimed that neither they have imported the PUC from the subject country nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

Basis for Alleged Dumping

Normal value

7. The Applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy and normal value should be determined as per the paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods. The Applicant has claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China, normal value of the Subject Goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

8. The Applicant has claimed that EU may be taken as a market economy third country for construction of normal value for China PR and has provided information regarding the selling price from Belgium to Germany.

9. All interested parties are advised to offer their comments on this issue within 30 days from the date of issuance of initiation notification. Pending detailed examination of the claim of EU as a surrogate country for China for this investigation, the Authority, for the purpose of initiation of the present investigation, has taken the selling price from Belgium to Germany for determining the normal value of China PR.

Export Price

10. The Authority has computed the export price for the subject country based on the DGCIS transaction wise import data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges and port expenses.

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin in respect of the PUC from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the PUC are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed

and cash flow as a result of increase in imports of PUC at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. Applicant has also claimed that there is a further threat of injury to the domestic industry in view of significant rate of increase in imports from China, significant capacities of subject goods in China and depressing effect of import prices on domestic selling prices. There is sufficient prima facie evidence that the injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury and in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

14. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

15. The Applicant proposed the Period of Investigation (hereinafter also referred to as POI) 01st April 2019 to 30th September 2019 (6 months). The Authority has also considered the POI as 01st April 2019 to 30th September 2019 (6 months). The injury investigation period will cover the period 2016-17, 2017-18, 2018-19 and POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

17. Known exporters in the subject country, their government through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. The information/submission may be submitted to :

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi – 110001

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

29. In terms of Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority